POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2020/अंक 10

मासिक प्रेषण दि. 8 अक्टूबर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 अक्टूबर, 2020 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! कोरोना जैसी महामारी ने देश और दुनिया के अधिकतर देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका असर इन सभी देशों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में भी देखने को मिल रहे हैं।

हमारे देश में इसका असर यहां की विविधता और ग्रामीण शहरी व्यवस्था में रहने वाले नागरिकों के संदर्भ में अन्य देशों से बहुत अलग है, ऐसे में हमें भारत की विविधता और सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना से फैली महामारी से लड़ना है।

इससे लड़ते हुए लोकल से वोकल होने की जो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है वह भारत की सामाजिक अवधारणा में वर्षों से रही है। उदारीकरण और बढ़ते वैश्विक अर्थव्यवस्था के दबाव में उस पर कभी ध्यान ना सरकारों द्वारा दिया गया न ही नागरिकों ने इसे समझा। अब जब दुनिया के सामने एक आपदा है तो उसे वह सब अवधारणा याद आने लगी है जिसे कभी वो समझते हुए भी दर किनार करता रहा है।

आज अगर गांधीदर्शन पर गौर किया जाए तो स्वदेशी अपनाओ से लेकर स्वालंबी और आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिखेगा, वही आज के समय की जरूरत है।

स्वास्थ्य सुविधाओं की मार खा रहे भारत के गांव और कस्बों में हालात कैसे होंगें यह हम सभी बेहतर जानते हैं इसे बोलकर और लिखकर स्वंय को निराशा की स्थिति में ले जाने का समय नहीं है, जो है उसी में इस संकट से लड़िए और सरकार द्वारा जारी नियमों के पालन के साथ उनका सम्मान भी एक सच्चे देशभक्त की पहली कोशिश होनी चाहिए।

फिलहाल वक्त लोकल से वोकल होने का है तो आस-पास के लोगों से सामान खरीदिए उनकी सहायता कीजिए और जो आत्मनिर्भर है वो दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे ना कि उनका ही हिस्सा खाने को लालायित दिखे।

स्कूल कैंटीन और उसके 50 मीटर के दायरे में नहीं बिकेंगे जंकफूड

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्कूल कैंटीन और स्कूल परिसर से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री और विज्ञापनों पर रोक लगा दी है।

एफएसएसएआई ने यह कदम बच्चों को सुरक्षित और पोष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए उठाया है। प्राधिकरण ने स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार नियम-2020 को लागू किया है।

एफएसएसएआई ने कहा कि इन नियमों को लागू करने से पहले जंक फूड निर्माताओं, स्कूल प्रबन्धकों सहित सभी पक्षों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। नियमों अनुसार जिन खाद्य पदार्थों में वसा या ट्रांस-वसा या ज्यादा चीनी, नमक होता है, उन्हें स्कूल कैंटीन, मैस, छात्रावास के रसोई या स्कूल के 50 मीटर के दायरे में बच्चों को नहीं बैचा जा सकता है। इसमें ऐसे खाद्य पदार्थों के विज्ञापन पर भी रोक है।

चारागाह से अतिक्रमण हटाने के निर्देश

हाईकोर्ट ने पचपदरा तहसील के दो गांवों में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पूर्व में दिए गए आदेशों की पालना तय करने के निर्देश के साथ निस्तारित कर दी।

मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति तथा न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता नरपतसिंह राजपुरोहित द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद कहा कि इसकोर्ट ने पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पत्र याचिका में चारागाहों का संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। ऐसे स्थलों पर किए गए अतिक्रमण हटाने को कहा था। खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के पूर्ववर्ती आदेशों की पालना में सार्वजनिक चारागाह पर अतिक्रमण पाए जाएं, तो उन्हें हटाया जाए।

उद्यमी को मार्गदर्शन की जरूरत

महिलाओं में उद्यमिता बढ रही है। महिला उद्यमियों को लॉचिंग के लिए मंच की जरूरत है। यह कहना है नेशनल वीमन्स चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज की जयपुर सिटी की काउसिंल की अध्यक्ष मालती जैन का।

उन्होंने एक वेबिनार में बताया कि नेशनल वीमन्स चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज को ज्ञान, सलाह, वित्त, प्रशिक्षण और बी2बी सहयोग के लिए सामूहिक पहुंच का लाभ देने में मदद करेगा। नीतिगत सुझावों पर सरकार के साथ अनुसंधान और कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की सलाह के तहत कई गतिविधियों का आयोजन होगा।

कोरोना महामारी के बावजूद सतत् विकास के पुनर्निर्माण में अवसर है - विशेषज्ञ

कोरोना महामारी के कारण सतत् विकास के अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हालांकि विशेषज्ञों को इसमें अवसर दिखाई दे रहा है। महामारी बहुत-सी योजनाओं को निर्माण करने का अवसर प्रदान करती है, जो कि वर्तमान परिदृश्य को बदल देगी, खपत और उत्पादन के पेटर्न को अधिक मजबूती प्रदान करेगी। उक्त विचार विशेषज्ञों ने 'कट्स' द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2020 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय वेबिनार में व्यक्त किए।

भारत में विभिन्न राज्य सतत् उपभोग और उत्पादान भी दिशा में कदम बढ़ा रहे है, जो कि सतत् विकास लक्ष्यों के उद्देश्य-12 को इंगित करता है। हालांकि बहुत-सी जगह से सतत् उपभोग और उत्पादन के लिए किए गए कार्यों को रिपोर्ट में नहीं किया जा रहा है, जिससे देश की छवि सतत् उपभोग और उत्पादन को लक्ष्यों को प्राप्त करने में विपरीत दिखाई दे रही है। उक्त विचार अर्चना दत्ता, परियोजना समन्वयक, स्विच एशिया ने व्यक्त किए।

वेबिनार के प्रारम्भिक उद्बोधन में 'कट्स' के निदेशक, जार्ज चेरियन ने कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी हितधारकों को द्वारा जब तक इस दिशा में काई ठोस प्रयास नहीं किए जाएंगें, तब तक सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है।

वेबिनार में अन्य वक्ता ईवा आइड्र स्ट्रोम, निदेशक, इकोलेबलिंग और ग्रीन कंजप्शन विभाग, स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन ने कहाकि जलवायु परिवर्तन पूरे समाज के उपभोग में बदलाव का प्रमाण है।

वेबिनार में केरल के पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव डा. उषा टाइटस ने स्वीकार किया कि समग्र सतत् विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में केरल राज्य शीर्ष पर है, लेकिन हम यह भी कह सकते है कि सतत् विकास लक्ष्य-12 के संबंध में निश्चित रूप से शीर्ष पर नहीं है।

वेबिनार में केरल इंस्टिट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के महानिदेशक डा. जाय एलामन ने सतत् विकास लक्ष्य-12 एवं अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय सरकारों को सशक्त एवं विभिन्न विभागों को स्वीकृत करने के महत्व को उजागर किया। वेबिनार में 12 देशों एवं भारत के 23 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुर में

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है। इस पेड़ पर कुल 35 सोलर प्लेटे लगाई गई है। इस पेड़ की लागत 7.5 लाख रुपए है। दावा किया जा रहा है कि इससे करोड़ों रुपए की आय भी होगी।

यह पेड़ वर्ष में 12 से 14 हजार यूनिट ग्रीन ऊर्जा का उत्पादन का उत्पादन करेगा, जो वातावरण में कार्बन को जाने से भी रोकेगा। केन्द्रिय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर ने अपनी आवासीय कॉलोनी में इसे लगाया है।

सिखा रही है आत्मरक्षा के गुर

राजसमन्द जिले की चार महिला पुलिसकर्मियों ने पहले जूडो करांटे और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और अब वे महिलाओं सशक्त बना रही है। अब तक दो हजार महिलाओं को आत्मरक्षा की गुर सीखा चुकी है। महिला पुलिसकर्मी सुनीता चौधरी, प्रियंका वर्मा, पुष्पा मेघवाल और सरोज जटिया को पुलिस विभाग की ओर से एक अवसर दिया गया। उसके बाद उन्होंने जूड़ों करांटे और मार्शल आर्ट को मिलाकर एक पैकेज बनाया।

इसके बाद वे महिलाओं और छात्राओं को ड्यूटी के अलावा प्रशिक्षण देने लगी। सुनीता चौधरी बताती है कि उन्होंने स्कूल के अलावा महिला समूहों को भी आत्मरक्षा के गुर सिखाये हैं। उन्होंने जिले के राजसमन्द, देवगढ, कैलावा आदि क्षेत्रों की महिलाओं और छात्राओं को ट्रेनिंग दी हैं।

भारत का पहला सीएनजी बायो पंप

गुजरात में बनासकांठा के दामा गांव में भारत का पहला सीएनजी बायो पंप प्रारम्भ हो गया है। यहां गाय और भैस के गोबर से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) तैयार की जाएगी।

उत्तर गुजरात के पशुपालकों से गायों का दूध एकत्र करने के काम में जुटी बनास डेयरी ने यह प्लांट स्थापित किया है।

टिड्डी के लिए अब नीम का बायो पेस्टिसाइड

बीकानेर स्थित एशिया के एकमात्र टिड्डी अनुसंधान केन्द्र फील्ड स्टेशन फॉर इनवेस्टिगेशन ऑफ लॉकस्ट (एफ.एस.आई.एल.) ने टिड्डी दल से मुकाबले के लिए नीम की निंबोली से बायो पेस्टिसाइड तैयार किया है, जिसका विभिन्न परिस्थियों में परीक्षण किया जा रहा है। यह पेस्टिसाइड किसान स्वयं बनाकर फसलों पर स्प्रे कर सकेंगे। इसका असर दो से तीन दिन तक रहेगा, तब तक टिड्डी दल स्वंय ही अन्य स्थानों पर उड़ जाएगा। वर्तमान में टिड्डी मारने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, जिसके उपयोग से एक सप्ताह तक फसल नहीं काट सकते।

ऐसे बनाया पेस्टिसाइड-10 किलो निंबोली को रात भर पानी में भिगोकर रखते है जिससे उसका पल्प निकल जाता है और बीज अलग कर देते हैं। सूखे बीजों का पाउडर बनाकर दस लीटर पानी में घोल लेते है। इसमें 250 ग्राम सर्फ मिलाकर एक दिन बाद छान लेते है। फिर इसमें 100 लीटर पानी मिलाकर खेती में स्प्रे करते हैं। यह स्प्रे पत्ती से लेकर तने तक होना चाहिए।

कोरोना महामारी में जैविक उत्पादों/ जैविक खेती की भूमिका पर वेबिनार का आयोजन

'कट्स' जयपुर द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2020 को एब वेबिनार का अयोजन किया गया। जिसका विषय 'कोरोना काल में जैविक उत्पादों/जैविक खेती की भूमिका रखा गया। वेबिनार के प्रारम्भ में 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने बताया कि कोरोना काल में जैविक खेती के उत्पादों की मांग बढ़ी है, जो कि जैविक खेती के लिए अच्छा अवसर है। सक्सेना ने बताया कि इस विषय पर चर्चा हेतु वेबिनार में डा. एस.के.शर्मा, डा. ए.के.शर्मा, रोहित जैन एवं वीरेन्द्र परिहार को आमंत्रित किया गया।

किसान बना रहे हल्दी के कैप्सूल

कोरोना महामारी के चलते हल्दी और अदरक की मांग 200 फीसदी तक बढ़ी है। गुजरात राज्य के आणंद जिले के किसान देवेश पटेल ने हल्दी अदरक के कैप्सूल लॉन्च कर दिए।

इससे वे तीन गुना ज्यादा कमाई कर लोगों को रोजगार भी दे रहे है। देवेश 35 बीघा जमीन पर जैविक हल्दी-अदरक पैदा कर रहे है।

प्रेरणा बनी 55 वर्ष की स्ट्राबेरी वाली चाची

55 वर्ष की उम्र में स्ट्राबेरी की खेती करना शुरू किया और आज न सिर्फ इसमें अच्छी खासी कमाई कर रही है, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी स्ट्राबेरी की खेती करना सीखा रही है। जबलपुर जिले के भीटा गांव की राजकुमारी, जो कुछ समय पहले तक बमुश्किल गुजारा कर पाती थी तथा पढी लिखी भी नहीं है, लेकिन स्ट्राबेरी की खेती का हुनर महिलाओं को सिखाती है।

राजकुमारी के पास महज डेढ एकड़ जमीन है, उन्होंने इस जमीन पर कुछ हटकर करने की ठानी। शुरूआत में उन्होंने कृषि विभाग के विशेषज्ञों से मदद ली। उनके मार्गदर्शन में सब्जी की खेती शुरू की। मुनाफा होने पर हौंसला बढा तो विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में स्ट्राबेरी की खेती शुरू कर दी। अब वे किसी की मेंटर है तो कोई चाची कहकर बुलता है। वे भी बढी लगन से सबको सिखाती है।

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 के महत्वपूर्ण प्रस्ताव

कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने और निजी वितरण कंपनियों को बढावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में 17 अप्रेल, 2020 को विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 प्रस्तुत किया गया है। इस लेख के माध्यम से हम उपभोक्ताओं से सरोकार रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में बता रहे हैं।

विधेयक द्वारा केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से अक्षय स्त्रोतों से बिजली उत्पादन को बढावा देने के लिए एक राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति तैयार करेगी। संशोधन के अनुसार एक अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (प्राधिकरण) की स्थापना भी की जाएगी जो बिजली उत्पादक कंपनियों और डिस्कॉम्स के बीच पैदा हुए विवादों का निपटारा करेगी।

इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण संशोधन के अनुसार, केन्द्र सरकार, अप्पेलेट ट्रिब्यूनल के सदस्यों, केन्द्रीय आयोग, विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण, राज्य आयोगों और संयुक्त आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी। इससे इन संस्थाओं में चयन के विषय पर राज्य सरकारों का प्रभाव कम हो जायेगा। इसके अलावा विद्युत वितरण में छिजत कम करने और गुणवत्ता बढाने के लिए, वर्तमान में काम कर रहे डिस्कॉम्स, आपूर्ति के अपने क्षेत्र के भीतर, एक फ्रेंचाइजी या फिर एक छोटी इकाई की नियुक्ति कर सकते हैं।

उपभोक्ताओं से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मुद्दों में, क्रॉस सब्सिडी को कम करना और उपभोक्ताओं को डी.बी.टी. के द्वारा सब्सिडी देना भी प्रस्तावित है। संशोधन के अनुसार डिस्कॉम्स को राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किये गए गए नये टैरिफ को 60 दिनों के भीतर लागू करना होगा। कुछ प्रगतिवादी सुझावों के बावजूद संशोधन को राज्यों से काफी विरोध झेलना पड़ा है। इसलिए उपभोक्ता संघटनों को इन संशोधनों के प्रभावों पर विचार-विमर्श करने के बाद अपने विचारों को मीडिया के माध्यम से राज्य और केन्द्र सरकार को अवगत कराना चाहिए।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485